

Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding the irrigation and purchase of Paddy crop in Bihar

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): सभापति महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र सहित पटना जिला के किसान, जो अन्नदाता हैं, उनकी समस्या की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ।

महोदय, पटना जिले में पिछले वर्ष की तुलना में धान की उपज अधिक हुई है, परंतु दुर्भाग्य है कि बिहार सरकार ने धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य पिछले वर्ष के मुकाबले 23 परसेंट घटाने का काम किया है । पिछले साल लक्ष्य 2 लाख 81 हजार मीट्रिक टन था, जिसे 23 प्रतिशत घटाकर लक्ष्य 2 लाख 15 हजार 949 मीट्रिक टन कर दिया गया है, जिसमें सबसे कम पटना जिले में किया गया है । हालांकि उपज अधिक है, पर लक्ष्य कम करने का काम किया गया है, जो किसानों की समझ से परे है । अतः वहां के किसानों में बहुत आक्रोश है । लक्ष्य घटाने का मुख्य आधार यह होता है कि या तो सूखा पड़ा हो, या धान की रोपाई का आच्छादन पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ हो, परन्तु इन दोनों कारणों में से कोई भी कारण पटना जिले पर लागू नहीं होता है । अगर सूखा पड़ा होता, तो सरकार पंचायतों को सूखाग्रस्त घोषित करने का काम करती, लेकिन पटना जिले की एक भी पंचायत सरकार द्वारा सूखाग्रस्त घोषित नहीं की गयी है ।

महोदय, इस वर्ष सरकार ने सभी जिलों के समानुपातिक लक्ष्य घोषित किए हैं । यानी जहां नहरीकृत सिंचाई व्यवस्था है और जहां गैर-नहरीकृत सिंचाई की व्यवस्था है, दोनों में बिहार सरकार ने एक ही तरह के उत्पादन का मानक माना है, जो युक्तिसंगत नहीं है । हमारे यहां पूरी सिंचाई होती है । कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है । ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप कृपया बैठ जाइए । यादव जी, आप बोलिए । इनका कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है । ...*

... (व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव: सर, उत्पादन का मानक कम है, जो युक्तिसंगत नहीं है । सोन नहर प्रणाली से सिंचित शाहाबाद के सभी जिलों को 'धान का कटोरा' कहा जाता है । उन सभी जिलों का लक्ष्य पिछले साल से कम कर दिया गया है । केवल पटना में ही नहीं, बल्कि अन्य जगहों पर भी किसानों के प्रति सरकार अन्याय कर रही है ।

महोदय, किसानों में घोर आक्रोश है । कुछ विरोध औरंगाबाद जिले में हुआ ।... (व्यवधान) वहाँ लक्ष्य पूर्ति हो गई ।... (व्यवधान) परन्तु पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, सासाराम आदि जिलों

के लक्ष्य में सुधार नहीं किया गया है ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करे ताकि धान अधिप्राप्ति लक्ष्य में सुधार हो और किसानों द्वारा उत्पादित धान की पूरी खरीदी हो सके । मेरे संसदीय क्षेत्र में किसान उग्र हैं, वे आन्दोलन कर रहे हैं । पूरी की पूरी व्यवस्था चौपट हो गई है ।... (व्यवधान)